

प्रेषक

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग 2

देहरादून, दिनांक 25 मई, 2007

विषय: जनपद उत्तरकाशी में धरारू बैण्ड से नगियारी दिखोली गरगाँव मोटर मार्ग की पुनरीक्षित स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (ग.क्षे) लोक निर्माण विभाग पौड़ी के पत्र सं०- 6103/01 (55) यारा-पर्व/06 दिनांक 20.11.2006 के संदर्भ में एवं शासनादेश सं०-59/लो०नि०-2/2004-41(प्रा.आ.)/2003 दिनांक 22 जनवरी, 2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त कार्य हेतु रु० 40.40 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2003-04 में रु० 3.00 लाख के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। विधान सभा आश्वारसन समिति की बैठक में दिनांक 24.8.2006 को दिये गये कारण कि मार्ग पर मिट्टी बहुत बलुई तथा वहाँ पर दीवार बनानी पड़ेगी तथा आगणन के प्रतिवेदन में मार्ग के 0.650 किमी० में उँची तथा अत्यधिक कठोर चट्टान होने के कारण एच.पी.बैण्ड एवं आवश्यक स्थानों पर पक्की दीवाल का निर्माण तथा 800मी० लम्बाई में सोलिंग एवं पक्की गाली का प्राविधान की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उपलब्ध कराये गये अवशेष कार्य के रु० 44.86 लाख के आगणन पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रूपये 39.05 लाख (रूपये उन्नालीस लाख पाँच हजार मात्र) की लागत की प्रशासकीय तथा रु० 3.00 लाख की धनराशि की व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए शासनादेश सं०-59/लो०नि०-2/2004-41(प्रा.आ.)/2003 दिनांक 22 जनवरी, 2004 द्वारा क्रमांक सं०-22 पर प्रदान की गई स्वीकृति में रु० 40.40 लाख की मूल स्वीकृति को सम्मिलित करते हुए कुल (रूपये 40.40+39.05)

रु० 79.45 लाख (रु० उन्नासी लाख पैतालीस हजार मात्र) की लागत की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं।

1. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि पुनरीक्षित लागत में इस कार्य को पूर्ण करा लिया जायेगा तथा अब इसके लिए पुनः कोई भी अतिरिक्त वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी। वित्तीय वर्ष 2003-04 में व्यय हेतु दी गई धनराशि रु० 3.00 लाख की स्वीकृति में उक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रु० 76.45 लाख कार्य की आवश्यकतानुसार बालू निर्माण कार्य की गद से निर्वर्तन पर रखी गई धनराशि से आवश्यकतानुसार वहन किया जायेगा।

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए आगणन में प्राविधानित समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग की प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराना होगा।

(हस्ताक्षर)

5. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भूमि निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
6. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
7. निर्माण सामग्री को क्रय करने से पूर्व स्टोर पर्यज नियमों का पालन करने के साथ-2 नियमानुसार विधिवत निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा इसकी पुष्टि स्थल साईट बुक में भी इंगित कराया जाना समीचीन होगा। उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।
8. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
9. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।
12. कार्य को समयबद्ध करते हुए अधीक्षण अभियन्ता उत्तरकाशी एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा समय-2 पर स्थल निरीक्षण करते हुए प्रत्येक 15 दिन के भीतर कार्य की प्रगति आख्या से शासन को अवगत कराया जायेगा।
13. उक्त योजना पर व्यय संगत मद में (मार्ग के बालू कार्य) के निवर्तन पर रखी गई धनराशि से आवश्यकतानुसार अपने स्तर से ही किया जाये।
14. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-103/XXVII(2)/2007 दिनांक 25 मई, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

संख्या- 1596
(1)/111-2/07 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय गौटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
5. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. अधीक्षण अभियन्ता, छठवां वृत्त, लो.नि.वि., उत्तरकाशी।
9. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
10. लोक निर्माण अनुभाग-2/3 उत्तराखण्ड शासन/ गार्ड बुक।

आज्ञा से
प्रदीप सिंह रावत
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।